>

Title : Need to give approval to a pilot scheme for computerization of ration cards for disbursal of cash amount to BPL families in Hardoi and Lakhimpur Khiri districts of Uttar Pradesh.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : महोदय, बी.पी.एल तथा अन्त्योदय परिवारों को सस्ता अनाज देने के लिए भारत सरकार करीब 32,700 करोड़ रूपया फूड सब्सिडी देती है। परन्तु गरीबों तक केवल 20 प्रतिशत पैसा पहुंचता है। मैंने पिछले साल लोक सभा में मामला उठाया था, जिस पर भारत सरकार ने राज्यों को लिखा भी था।

इस स्थिति को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के दो जिलों हरदोई तथा लखीमपुर खीरी में बीपीएल परिवारों के सभी राशन कार्डों को कम्प्यूटराज्ड करके उन्हें अनाज के बजाय सब्सिडी का पैसा ही बैंकों द्वारा दे दिया जाये।

मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर उपरोक्त दो जिलों में अविलम्ब लागू कराए और यदि इसके अच्छे परिणाम आते हैं तो इसे पूरे देश में लागू कराए।